[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair]

Need for restoring full electricity supply to Dhanbad in Jharkhand by Damodar Valley Corporation

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA (Jharkhand) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to draw the attention of the Government towards the problems being faced by the people of Dhanbad due to cut in the supply of electricity by the Damodar Valley Corporation.

The Damodar Valley Corporation has curtailed 50 per cent of electricity supply to the Jharkhand State Electricity Board in general and to the Dhanbad district in particular. Due to the curtailment of electricity, supply of water to the Dhanbad district has been affected very badly. There is virtually a collapse in the water supply. This has aroused vociferous resentment among the people of Dhanbad.

Sir, Jharkhand is no the only State which owes dues. There are many other States which owe dues to the Damodar Valley Corporation to whom the DVC is still supplying uninterrupted electricity. The DVC has not curtailed or pruned their requirement. Then why is there such a harsh and step-motherly treatment with this infant State and that too at a time when the tortuous summer season has set in and is at its peak? You will appreciate that none can survive without water especially in summer.

Mr. Vice-Chairman, Sir, through you I would like to urge upon the Government to direct the DVC to restore full supply of electricity to Dhanbad. The matter relating to dues may be discussed across the table at the appropriate level and resolved amicably. Thank you.

Need to take effective measures for decreasing the burden of school bags on the children of the country

प्रो0 एम0एम0 अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश के बच्चों के ऊपर बढ़ते स्कूली बस्ते के बोझ को कम करने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

(उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं।)

महोदया, मार्च 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रो0 यशपाल की अध्यक्षता मे देश के आठ शिक्षा-विदों की एक समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य था कि बच्चों पर बढ़ रहे स्कूली बस्ते के बोझ को कम किया जाए। इस समिति ने देश के विभिन्न छात्रों, संस्थाओं व

बुद्धिजीवियों से सलाह-मशविरा करके सरकार को जुलाई, 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से अधिक बुरा है न समझ पाने का बोझ। समिति ने स्कूली पुस्तकों को रटवाने के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए और बच्चों की पाठ्य-पुस्तकों को रोजाना घर पर ले जाने के बजाय स्कूल में रखने का सुझाव दिया था और यह कहा था कि नर्सरी कक्षाओं के दाखिले के लिए होने वाले टैस्ट व इंटरव्यू बंद होने चाहिए। लेकिन दाखिले की यह प्रक्रिया आज भी जारी है। छोटे-छोटे व कोमल बच्चों को होमवर्क के भार से बचाया जाए। इस समस्या के समाधान की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। प्राइमरी की कक्षाओं को गृह कार्य सिर्फ इतना दिया जाए कि वह अपने घर के वातावरण को खराब न कर सके। यह दुख की बात है कि दस वर्ष से ज्यादा व्यतीत हो जाने के उपरांत भी बच्चे को अपने से अधिक किताबों का बोझ उठाना पड़ता है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के बच्चे, जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, उनके हित में प्रो0 यशपाल समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

उपसभापति : दिल्ली के "बाल भारती स्कूल" ने बस्ते का वज़न कम कर दिया है। किताबों को कम करके वज़न कम कर दिया है। यह सब जगह होना चाहिए, आपकी बात ठीक है। हमारे एक नॉमिनेटिड मैम्बर थे, मिस्टर नारायणन, जिन्होंने "मालगुड़ी डेज़" लिखा था, उन्होंने भी यह बात उठाई थी। बहुत पहले की बात है।...**(व्यवधान)**... बच्चों पर ही भार है पूरे देश का। कुमारी मैबल रिबैलो।...**(व्यवधान)**... बस्ते का वज़न कम करना चाहिए, बहुत हैवी होते हैं।

प्रो0 रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, आप डायरेक्शन दीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन आना चाहिए। पूरा देश चाहता है कि बच्चों के बस्ते का वज़न कम हो।

उपसभापति : ठीक है, आपके कहने से डायरेक्शन दे दिया है कि सरकार ध्यान रखे कि बच्चों के बस्ते का वज़न कम करने का क्या तरीका हो सकता है।...**(व्यवधान)**... Our Parliamentary Affairs Minister is here. He will convey it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O.RAJAGOPAL) : Madam, in Special Mentions, Government naturally takes note of the points raised.

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is not the HRD Minister. So, he cannot do implementation. He can only convey it.

प्रो0 रामगोपाल यादव : अहलुवालिया जी को क्यों नहीं बना देते।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Ahluwaliaji can also convey it. He must have also carried burden on him.